

व्हाट्सएप को वनियमित करने संबंधी याचिका पर सुनवाई

सन्दर्भ

हाल ही में व्हाट्सएप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, अतः अब इस संबंध में सरकारी नियम बनाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में व्हाट्सएप पर आरोप है कि उसने अपनी सहयोगी सोशल नेटवर्कगि साइट फेसबुक से उपभोक्ताओं की नजिी जानकारी साझा की है, यह व्यक्ति के नजिता के अधिकार का उल्लंघन है।

महत्त्वपूर्ण बद्दि

- 2016 में लागू की गई नजिता संबंधी नई नीतिकाे तहत व्हाट्सएप, फेसबुक के साथ उपयोगकर्ताओं के डेटा साझा करता है। याचिकाकर्ता का कहना था कि इससे न सिर्फ उपभोक्ता का ब्यौरा, बल्कि उसकी नजिी बातचीत भी गलत हाथों में जा सकती है।
- प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि आप मुफ्त सेवा का उपयोग करते हुए नजिता के अधिकारों का दावा नहीं कर सकते, लेकिन बाद में जस्टिस खेहर और डी. वाई. चन्द्रचूड की बेंच ने इस मामले पर सरकार, भारतीय दूरसंचार नियामक, व्हाट्सएप एवं फेसबुक को नोटिस जारी करके इसका जवाब मांगा है।
- याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि भारतीय दूरसंचार नियामक इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाने में वफिल रहा है।

क्यों है विवाद?

- दुनिया भर में चर्चति एवं सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मैसेजिंग सेवा 'व्हाट्सएप' ने 26 सतिंबर, 2016 से अपने उपयोगकर्ताओं की जानकारी फेसबुक के साथ साझा करने का फैसला किया था।
- हालाँकि, तब भी उपयोगकर्ताओं की जानकारी फेसबुक के साथ साझा करने के मामले में दलिली उच्च न्यायालय ने मैसेजिंग साइट व्हाट्सएप से कहा था कि वह 25 सतिंबर, 2016 तक के उपयोगकर्ताओं की जानकारी फेसबुक से साझा नहीं करे। वदिति हो कि इस तारीख से एप्पलीकेशन की नजिता की नई नीतिलागू हो गई है। अतः नई नीतिलागू होने के बाद के उपयोगकर्ताओं की जानकारी साझा की जा सकती है।
- दरअसल, अब इस नई याचिका में दलिली उच्च न्यायालय के उस फैसले को भी चुनौती दी गई है जिसमें न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई नीतियाँ लागू होने के बाद उपयोगकर्ताओं की जानकारी साझा करने को सही ठहराया था।

नषिकर्ष

- वस्तुतः नजिता का आशय किसी व्यक्ति को यह तय करने का अधिकार कि किस हद तक वह दूसरों के साथ स्वयं को साझा करना चाहता है। नषिचति रूप से किसी को भी इस बात का हक है कि वह स्वयं को सबसे अलग कर ले और किसी को भी उसकी नजिी ज़िंदगी में तकने-झाँकने का अधिकार न हो।
- नजिता का अधिकार (Right to privacy) के मुताबकि कोई भी इंसान किसी भी व्यक्ति के हर उस मामले में दखल देने का अधिकार नहीं रखता, जो मामला किसी व्यक्ति की नजिता या नजिी जीवन को प्रभावति करता है। अब, जब इस बहुचर्चति मामले में गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में आ चुकी है, तो उम्मीद की जानी चाहिये कि न्यायपालिका नजिता के अधिकार की सुरक्षा को नया आयाम देगी।